There are also understood to be asylum seekers in France, New Zealand, Norway, UK and USA. Their numbers and the reasons for granting asylum are not shared by these countries.

Indian troops on Sino-Indian border

774. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a likelihood of depletion of Indian troops on the Sino-Indian border as per the newsitem entitled "Troops cut likely on Sino-Indian border", which appeared in the 'Times of India', dated 26th May, 1992; and

(b) if so, what are the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) and (b) Government have seen the news item "Troops cut likely to Sino-Indian border" which appeared in the Times of India of 26 May, 1992 No agreement has been concluded between India and China so far on troop reductions in the border areas between the two countries. Specific confidence-building measures for the maintenance of peace and tranquillity in the border areas are being discussed by the Joint Working Group set up by India and China on the boundary question.

प्रधान मंत्री की जापान यात्रा

775. **श्री राम नरेश यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री की हाल ही की जापान यात्रा का उद्देश्य क्या था ;

(ख) इस उद्देश्य की पूर्ति में किस हद तक सफलता मिली है ; और

(ग) इस यात्रा का भारत की पंचवर्षीय योजना से क्या सम्बन्ध है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) भारत तथा जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ वर्ष में प्रधानमंत्री की 22 से 28 जून, 1992 तक की जापान की यात्रा एक सद्भावना यात्रा थी । यात्रा का विशेष उद्देश्य यह था कि दोनों देशों के बीच राजनतिक तथा आर्थिक विचार-विमर्श को बढ़ाया जाए और साथ ही समान हित तथा आपसी लाभ के क्षेत्रों का पता लगाया जाए ।

(ख) इस यात्रा से भारत और जापान ने आपसी हित चिन्ता के विभिन्न मसलों के संबन्ध में एक दूसरे को और अधिक समझा है । प्रधान मंत्री स्तर की वार्ता में जापानी पक्ष ने भारत के आर्थिक सुधारों को समर्थन देने की अपनी वचनबद्धता दोहराई तथा वर्ष 1992–93 के लिए 112 मिलियन येन लगभग 850 मिलियन अमरीकी डालर की सरकारी विकास सहायता देने का वचन दिया । प्रधान मंत्री ने सार्वभौमिक तथा भेद-भाव रहित अप्रसार के प्रति भारत की वचन-बद्धता को दोहराया । भारत तथा जापान इस मसले पर भविष्य में अनौपचारिक द्विपक्षीय बातचीत करेंगे ।

(ग) भारत को मिलने वाली जापानी विकास सहायता के अन्तर्गत भारत के आर्थिक विकास तथा योजनागत प्राथमिकताओं के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं । प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान जापान द्वारा विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं । इनमें आधारभूत संरचना का निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा पर्यावरण क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं । प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान जापान द्वारा घोषित सरकारी विकास सहायता उन परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई है जिनके अन्तर्गत भारत के योजनागत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं